विश्वामित्र का राजपत्र

THE GAZETTE OF VISHWAMITRA

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

राजगृह, बुधवार, 10 अगस्त, 2022|19 श्रवण, 1944

RAJAGRIHA, WEDNESDAY, 10 AUGUST, 2022|19 SHRAVANA, 1944

BY THE RASHTRADHYAKSH OF VISHWAMITRA

Rajagriha, the 10th August, 2022/Shravana 19, 1944 (Saka)

संसदीय कार्य मंत्रालय

राजगृह, 10 अगस्त, 2022/श्रवण 19, 1944 (शक)

[10 अगस्त 2022]

प्रशासक परिषद का गठन

I. परिषद का गठन:

1. प्रशासकों की परिषद या "प्रशासक परिषद" विश्वामित्र राज्य के विदेशी क्षेत्रों के प्रशासकों का बोर्ड होगा।

2. परिषद उन कानूनों को छोड़कर, जिनके लिए संसद या अन्य संवैधानिक संस्थानों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, राष्ट्र के विदेशी क्षेत्रों से संबंधित विकास और अन्य मामलों से संबंधित कानूनों पर चर्चा, प्रतिनिधि, कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।

II. परिषद की संरचना:

1. परिषद निम्नलिखित से बनी होगी:

    1) विश्वामित्र के राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी प्रदेशों के संप्रभु के रूप में

    2) विदेशी प्रदेशों के प्रशासक

    3) विदेश मंत्री, विश्वामित्र सरकार

    4) विदेश राज्यमंत्री, विश्वामित्र सरकार

    5) राज परिषद के एक सदस्य को परिषद के पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है और समय-समय पर महामहिम राष्ट्राध्यक्ष की ओर से उनके निर्देशानुसार कार्य करता है।

    6) प्रशासकों द्वारा नामित विदेशी प्रदेशों के उप प्रशासक (यदि कोई हो)

2. प्रदेशों के प्रशासक परिषद के मतदान सदस्य होंगे।

3. पद ग्रहण करने के मामले में सबसे वरिष्ठ प्रशासक को परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा जो परिषद के प्रमुख और परिषद के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष सरकार के समक्ष या महामहिम राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष तत्काल महत्व या ध्यान देने के मामलों को सौंपने के लिए जिम्मेदार होगा।

4. अध्यक्ष, समय-समय पर, जिम्मेदार मंत्रियों या अध्यक्ष द्वारा नामित राज परिषद के सदस्य को क्षेत्रों के मामलों के बारे में अद्यतन और सूचित कर सकता है।

III. परिषद की क्षमताएं और अक्षमताएं:

1. परिषद के पास विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन, शासन, नियुक्तियों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति होगी।

2. परिषद के पास निर्दिष्ट तिथियों को अनुमोदित करने, क्षेत्रीय सम्मानो के लिए नामांकन को मंजूरी देने और उन क्षेत्रों से संबंधित अन्य मामलों पर अधिकार होगा जिन पर आम ध्यान देने की आवश्यकता है।

3. परिषद क्षेत्रों के भीतर आंतरिक प्रशासन, संस्कृति, शिक्षा, व्यय, पर्यावरण, सूचना, प्रौद्योगिकी, सामाजिक मुद्दों, कृषि, बागवानी, पशुपालन, आदि विषयों पर कानूनों को मंजूरी देने, कानून बनाने और तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी।

4. परिषद के पास क्षेत्रों के लिए रक्षा, विदेश मामलों, वित्त, अर्थव्यवस्था, न्याय आदि से संबंधित कानून बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

IV. संशोधन:

1. परिषद बहुमत के मत के माध्यम से परिषद की स्थापना की अधिसूचना में संशोधन करने की मांग कर सकती है और ऐसा करने पर, वे अध्यक्ष द्वारा नामित राज परिषद के सदस्य को सूचित कर सकते हैं।

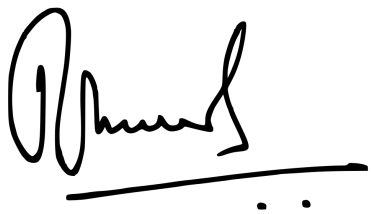

[10 August 2022]

CONSTITUTION OF THE ADMINISTRATOR'S COUNCIL

I. Constitution of the council:

1. The Council of Administrators or the "Administrator's Council" shall be the board of administrators of the overseas territories of the State of Vishwamitra.
2. The council shall be responsible to discuss, delegate, legislate laws pertaining to the development and other matters related to the overseas territories of the nation, except for those laws which require approval from the Parliament or other constitutional institutions.

II. Composition of the council:

1. The Council shall be composed of the following:
    1) The Rashtradhyaksh of Vishwamitra, as Sovereign of the Overseas Territories
    2) The Administrators of the Overseas Territories
    3) The Minister of External Affairs, Govt. of Vishwamitra
    4) The Minister of State for External Affairs, GoV
    5) One member of the Privy Council nominated by the President to act as an observer member of the council and to act on behalf of His Illustrious and Royal Majesty the Rashtradhyaksh from time to time as directed to them
    6) The Deputy Administrators of the Overseas Territories (if any), nominated by the Administrators
2. The administrators of the territories shall be the voting members of the council.
3. The most-senior administrator in terms of assumption of office shall be designated as the Chairperson of the Council who shall act as the Head of the Council and as the presiding officer of the council. The

chairperson shall be responsible for delegating matters of urgent importance or attention before the Government or before His Illustrious and Royal Majesty the Rashtradhyaksh.

4. The chairperson may also, from time to time, update and inform the Ministers-responsible or the member of the privy council nominated by the president about the affairs of the territories.

III. Abilities and disabilities of the council:

1. The council shall have the power to approve decisions on matters related to the administration, governance, appointments in the various territories.
2. The council shall have the power to approve designated dates, approve nominations to the territorial decoration and on other matters related to the territories which require common attention.
3. The council shall be responsible to approve, legislate and prepare laws on subjects - internal administration, culture, education, expenditure, environment, information, technology, social issues, agriculture, horticulture, animal husbandry, etc. within the territories.
4. The council shall have no jurisdiction in making laws related to the defence, external affairs, finance, economy, justice, etc. for the territories.

IV. Amendments

1. The council through a vote of majority may seek to amend the notification establishing the council and in doing so, they may inform the member of the privy council as nominated by the president.